

प्रेषक,

के० सी० मिश्र
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी
सम्बन्धित नगर पंचायत, उत्तरांचल
(संलग्न सूची के अनुसार)

वित्त अनुभाग - 1

देहरादून : दिनांक : 22 फरवरी, 2005

विषय : प्रथम राज्य वित्त आयोग, उत्तरांचल की संस्तुतियों के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों की समनुदेशन की रोकी गई 30 प्रतिशत धनराशि से 15 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

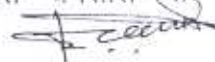
महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रथम राज्य वित्त आयोग, उत्तरांचल की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार राज्य की शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2004-05 में 70 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तथा 30 प्रतिशत धनराशि उनके वित्तीय तथा संस्थागत कार्य निष्पादन से सम्बद्ध कर रोकी गई थी। आयोग के प्रतिवेदन के प्रस्तर 21.5 (ग) के अनुसार आयुक्त कुमाऊँ मण्डल की संस्तुति पर राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के निर्णयानुसार 3 नगर पंचायतों को मानकों के आधार पर राजस्व वृद्धि की शर्त पूरी करने पर रोकी गई धनराशि की अवशेष 15 प्रतिशत धनराशि तथा नगर पंचायत दिनेशपुर को अधिक लोकतांत्रिक कुशल प्रशासन की दिशा में प्रगति हेतु 15 प्रतिशत धनराशि संलग्न विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए कुल धनराशि ₹0 1321000 (₹0 तेरह लाख इक्कीस हजार मात्र) संकमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संकमित की जा रही है:-

(1) स्थानीय निकायों को कुल देय वार्षिक धनराशि से रोके गये 30 प्रतिशत अंश से 15 प्रतिवेदन के प्रस्तर 21.5 के अन्तर्गत प्रस्तर 22.5 व 22.6 के अनुसार राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की संस्तुति पर अवमुक्त किया जा रहा है।

(2) संकमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा। संकमित की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिसके लिए संकमित की गई है। इस धनराशि से व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।



(3) नगर विकास विभाग संकभित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे। कोषागार से आहरित धनराशि का बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।

(4) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-3604-स्थायी निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन -आयोजनेत्तर-01-नगरीय स्थानीय निकाय-193-नगर पंचायतें/नोटिफाइड एरिया/कमेटी आदि-03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करें से समनुदेशन-00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

संलग्न :- यथोपरि।

भवदीय,

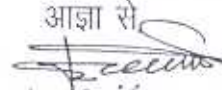
(के० सी० मिश्र)
अपर सचिव, वित्त

संख्या- 203 (1)/XXVII(1)/ 2005 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तरांचल।
3. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, निदेशालय, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5. निदेशक, कोषागार, वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरांचल।
7. विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
9. एन० आई० सी० सचिवालय, उत्तरांचल, देहरादून।

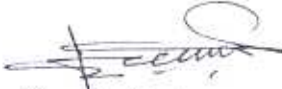
आज्ञा से


(के० सी० मिश्र)
अपर सचिव, वित्त

शासनादेश संख्या :- 203 /XXVII(1)/ 2005 दिनांक :: 22-फरवरी, 2005 का संलग्नक

(धनराशि हजार में)		
क0 सं0	नगर पंचायत का नाम	आवंटित 15 प्रतिशत धनराशि
1	2	3
1.	भीमताल	271
2.	द्वाराहाट	277
3.	धारचूला	358
4.	दिनेशपुर	415
	योग :-	1321

(रू0 तेरह लाख इक्कीस हजार मात्र)


(के0 सी0 मिश्र)
अपर रायिव, वित्त